



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 13, 2011/आश्विन 21, 1933

No. 217]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 2011/ASVINA 21, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2011

सं. 79/(आर.ई.-2010)/2009-2014

विषय : प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-I (2009-14) में क्लबिंग (पैरा 4.20) के प्रावधानों में संशोधन।

फा. सं. 01/94/180/234/एएम 12/पीसी-4.—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा, प्रक्रिया-पुस्तक, (खण्ड-I), 2009-2014 के पैरा 4.20 में तत्काल प्रभाव से संशोधन करते हैं। पैराग्राफ को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

4.20 क्लबिंग की सुविधा मामलों की सिर्फ विमुक्ति/विनियमन के लिए उपलब्ध होगी और आगे किसी आयात अथवा निर्यात की अनुमति नहीं होगी। इस सुविधा के लिए, विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए भी समान सीमा-शुल्क अधिसूचना के तहत प्राधिकार पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, 1-4-2004 को अथवा उसके बाद जारी प्राधिकार पत्रों के मामले में, विभिन्न सीमा-शुल्क अधिसूचनाओं के साथ अग्रिम प्राधिकार पत्र मिलाए जा सकते हैं। वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र को अग्रिम प्राधिकार पत्र के साथ भी मिलाया जा सकता है।

4.20.1 क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिनके कार्यक्षेत्र के अधीन प्राधिकार पत्र जारी किया गया है अथवा अन्य मामलों में विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) एक से अधिक अग्रिम प्राधिकार पत्र के सभी आयातों और निर्यातों की क्लबिंग के लिए एएनएफ 4घ में प्रस्तुत अनुरोध पर विचार करेगा बशर्ते कि आयातित निवेश का मानदण्डों के अनुसार उचित आकलन किया गया हो। इस प्रकार मिलाए गए प्राधिकार पत्रों का मूल्य संवर्धन, विदेश व्यापार नीति और उसके तहत बनायी गई प्रक्रिया में निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन और अलग-अलग प्राधिकार पत्रों पर लगाए गए मूल्य संवर्धन का औसत होगा। क्लबिंग के बाद, सभी प्रयोजनों के लिए, इन प्राधिकार पत्रों को एक प्राधिकार पत्र माना जाएगा और उसके बाद कमी, यदि कोई है, तो प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 4.28 की शर्तों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

4.20.2 हटा दिया गया है।

4.20.3 सिर्फ ऐसे अग्रिम प्राधिकार पत्रों को जोड़ा जा सकेगा जोकि सबसे पहले प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख से 36 माह के भीतर जारी किए गए हों जिन्हें आपस में मिलाया जाना है, चाहे ऐसे प्राधिकार पत्र वैध हैं अथवा नहीं।

- 4.20.4 क्लबिंग के बाद जहाँ कहीं, पहले के प्राधिकार पत्र निर्यात दायित्व अवधि के बाद निर्यात किया गया है, वहाँ निर्यात दायित्व में आई कमी का 0.5% संयोजन शुल्क के रूप में लगाया जाएगा।
- 4.20.5 उपर्युक्त पैरा 4.20.3 के प्रावधानों के बावजूद, एक्जिम नीति अवधि 1992-1997 एवं 1997-2002 अर्थात् 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 2002 के दौरान जारी किए गए प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की अनुमति होगी। यह सुविधा सिर्फ 31 मार्च, 2012 तक उपलब्ध होगी, जिसके बाद 31 मार्च, 2002 से पूर्व जारी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की अनुमति नहीं होगी। पूर्ववर्ती मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों की क्लबिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस संशोधन का प्रभाव : क्षेत्रीय प्राधिकारी अब अग्रिम प्राधिकारी पत्रों की क्लबिंग की अनुमति देंगे। यह एक विकेन्द्रीकरण का उपाय है। निर्यातकों को उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत शामिल मामलों में, विदेश व्यापार महानिदेशालय, मुख्यालय से संपर्क साधने की आवश्यकता नहीं होगी।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 13th October, 2011

No. 79/(RE-2010)/2009-2014

Subject : Amendment in the provision of Clubbing (Para 4.20) in HBP Vol. I (2009-14)

F No. 01/94/180/234/AM 12/PC-4.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Director General of Foreign Trade hereby amends Para 4.20 of the Handbook of Procedure Vol. I (2009-14) with immediate effect. The paragraphs will read as follows :

- 4.20 Facility of clubbing shall be available only for redemption/regularisation of cases and no further import or Export shall be allowed. For this facility, authorisations are required to have been issued under similar Customs notification even pertaining to different financial years. However, in case of Authorisations issued on or after 1-4-2004, Advance Authorisations with different customs notification can be clubbed. Advance authorisation for annual requirement can also be clubbed with the advance authorisation.
- 4.20.1 RA, under whose jurisdiction authorisation is issued or DGFT (HQs) in other cases, shall consider a request in ANF 4D for clubbing all imports and exports of more than one Advance Authorisation provided imported inputs are properly accounted for as per norms. Value addition of the authorisations so clubbed shall be average of minimum value addition prescribed in FTP and Procedure laid thereunder, imposed on individual authorisations. Upon clubbing, authorisations shall, for all purposes, be deemed to be one Authorisation and thereunder shortfall, if any, shall be regularized in terms of para 4.28 of HBP v1.
- 4.20.2 Deleted
- 4.20.3 Only such Advance Authorisations shall be clubbed which have been issued within 36 months from the date of issue of the earliest Authorisation that is sought to be clubbed, whether such Authorisations are valid or not.
- 4.20.4 Upon clubbing wherever exports are accounted beyond the EO period of the earlier Authorisation, a composition fee of 0.5% of the shortfall in EO shall be levied.
- 4.20.5 Notwithstanding provisions of para 4.20.3 above, clubbing of the Authorisations issued during Exim Policy period 1992-1997 & 1997-2002 i.e. 1st April, 1992 to 31st March, 2002 be allowed. This facility will be available only till 31st March, 2012, thereafter no clubbing of Authorisations issued before 31st March, 2002 shall be allowed. No clubbing of erstwhile Value Based Advance licence shall be allowed.

Effect of this Amendment : Regional Authorities (RAs) would now allow clubbing of Advance Authorisations. This is a decentralising measure. The exporters will not be required to approach DGFT Headquarters in cases covered under the above categories.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade